

पत्रांक 4255/36 सी
सेवा में,

दिनांक रानीखेत 07/11, 2023.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/258/2015/एफ.सी./970 दिनांक 11.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.480 है० अर्थात 6.500 है० ग्राम सड़का सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड रानीखेत द्वारा प्रत्यावर्तित 3.24 है० भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल 6.480 है० ग्राम सड़का की भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1641591.00 लाख जमा कर दी गयी है तथा 6.48 है० सड़का की भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दी गयी है, जिसकी खतौनी मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (विभाग द्वारा) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान एन.पी.वी. की धनराशि ₹ 2737800.00 लाख जमा कर दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान दरों से एन.पी.वी. में बढ़ोतरी हुई तो बढ़ी हुई दरों से एन.पी.वी. जमा कर दी जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उन्ही के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान धनराशि तथा अन्य निधिया तथा क्षतिपूरक की कुल धनराशि ₹ 4379391.00 लाख (CAMP) के खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः पेज-2 पर

4

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Sap plantation की जाएगी। इस आशय की तस्वीरें बढ़ता प्रेषित की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा (Central Verge) विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में (Sap Plantation) की जाएगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	State Govt. will provide the original hard copy of FRA certificate for diversion of 3.24 ha forest land.	सत्यापित प्रमाण पत्र (F.R.A.) इस कार्यालय के पत्रांक 1400/अजी. वि. 24.07.2021 द्वारा तीन प्रतियों में प्रेषित किया गया है। पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
7	State Govt. will submit CA site suitability certificate for Indaka Crvli & Sengam instead of Elimara Crvli & Sengam. The document may also be uploaded in online Part-II and name of CA site shall be entered in Part-I, of online Part-I.	सत्यापित प्रमाण पत्र (F.R.A.) इस कार्यालय के पत्रांक 1400/अजी. वि. 24.07.2021 द्वारा तीन प्रतियों में प्रेषित किया गया है। पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विधिवतित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की अनुमति आशय विधिपूर्वक स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

प्रमाण :- उपरीक्तानुसार 3 प्रतियाँ में।

(डॉ. श्रीमती चाम्पक)
अतिरिक्त अधिकारी,
आन्धीय खण्ड, जल विभाग, रायचौल।

पत्रांक 4255/3648 सहायक अधिकारी

अतिरिक्त सहायक अधिकारी (प्रमाण), आन्धीय खण्ड, जल विभाग, रायचौल को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. श्रीमती चाम्पक)
अतिरिक्त अधिकारी,
आन्धीय खण्ड, जल विभाग, रायचौल।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.com



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.com

पत्र सं० 08वीं/यू०सी०पी०/०६/२५८/२०१५/एफ०सी०/१७०

दिनांक 11/09/2017

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - अल्मोड़ा में रापड जीनापानी मझेडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1168/X-4-15/1(606)/2015 दिनांक 03.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10075/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरांत व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- अल्मोड़ा में रापड जीनापानी मझेडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.24 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.480 अर्थात् 6.500 हे० ग्राम- सडका सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के वाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide the original hard copy of FRA certificate for diversion of 3.24 ha forest land.
7. State Govt. will submit CA site suitability certificate for Sadaka Civil & Soyam instead of Dhura Civil & Soyam. The document may also be uploaded in online Part-II and name of CA site may be corrected at para-L of online Part-I.

अध्यापति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
राज्य/खण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून



उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
 2. एन.पी.वी. की दरों में अगर वढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वढी दरों पर एन.पी.वी. देने को लिए बाध्य होगा।
 3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु घनित 6480 अर्थात् 6.500 है० ग्राम- साइका सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
 6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये एक्जोर्ट गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
 7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
 8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
 9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 353 से अधिक न हो।
 10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने ध्य पर वन विभाग ५ रख-रेख में strip plantation की जाएगी।
 11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवों का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय थनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
 12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

अग्र्याप्रति सत्यापित

B. Man
सहायक अभियन्ता
रान्ता खण्ड लो० नि० डि०
रान्ताखंड

Man
गवदीय
(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

संह
लेक

क-

पर

कृति
कारी,
वेचार
स्थान
निर्माण
कृति

अर्थात्

जगाकर

Verge

ion की

देने के

ी प्रकार

वं स्टॉफ

64 H.

2279

36 (A)

110812

अतः सप्त शिक्षाधिकारी, रानीखेत की सरसुति के आधार पर विचारन अनुष्ठा-

दिनांक 90/07/2021

110300

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोडा

संख्या- 6084 / ग्यारह-- 20 / 2020-21. दिनांक: 23 जुलाई, 2021

(नितिन' सिंह भदौरिया)
जिला अधिवक्ता, अन्वयोः

A

8A कनवाल
समीन

प्रतिलिपि निम्नाकिंतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा।

आभीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा ।

સુખ જિલ્લાધિકારી, રાણીચેત, જાનપદ અભ્યોદય ।

અનિશ્ચયી અગિયન્તા, પ્રાન્તીય સ્વપ્ન, લાંબાનિંદા, સમીચ્છત ।

तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता (द्वितीय), प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राणीखेत।

प्रभाती अभिकान्ति, चन अग्रप्राप्त, गिरा ~~कामाक्षी~~, अलगोडा ।

(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिवक्ता, अ

ρ. 7. 6

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा से रायड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.24 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सहाय सार से यदि कुछ वर्तमान भूखण्ड की दूरी से बहोतरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


अवर सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण सार, लोहापिछिया,
रायड़खेत


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण सार, लोहापिछिया,
रायड़खेत


अतिरिक्त अभियन्ता,
ग्रामीण सार, लोहापिछिया,
रायड़खेत

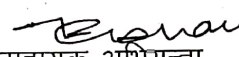
प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में रापड़ जीनापानी मझेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.24 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर लोक निर्माण विभाग अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा।


Ameen


अपर सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (IN Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16 FP/UK/ROAD/16102/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/16102/2015 Construction of motor road to connect Dev Singh Kwarbi's village Kamechina	ROAD161022015369	6116102369	02 Aug 2017	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 487822/-, trees effected of 10 times by the proje: 530000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1017822/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 19 Dec 2017 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 21 Dec 2017 On Transaction Date 01 Apr 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/1211181241213144R4DemandNoteDeSingh.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD161022015369)
17 FP/UK/ROAD/18386/2016 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/18386/2016 Extension of Pall Naduli motor road to Manjoorkhan motor road	ROAD183862016342	6118386342	15 Sep 2017	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 221737/-, trees effected of 10 times by the proje: 570000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 791737/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 19 Dec 2017 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 21 Dec 2017 On Transaction Date 01 Apr 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/12111812012131H9ZUDemandNotePallNaduliJakhdiMowadi.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD183862016342)
18 FP/UK/ROAD/10075/2015 Viewreport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10075/2015 Construction of Rapar Jeenapani Majera Motor Road	ROAD100752015268	6110075268	11 Sep 2017	CA: 1641591/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 2737800/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4379391/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by 22 Mar 2018 Nodal Officer On Bank Name Corporation Bank Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 22 Mar 2018 On Transaction Date 28 Mar 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/311221214121200QZUDemandRaparJeenapaniMajera.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD100752015268)

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा से रापड़- जीनापानी- मझौड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

इन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जनपद प्रति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गंगोड़ा (रापड़)
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
जनपद प्रति प्रमाण पत्र उपरोक्त

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु
..... X हेतु आवंटित वन भूमि X हेतु निर्मित सड़क भूमि 2.160 हेतु वन पंचायत भूमि 1.080 (हेतु) अर्थात् कुल 3.240
हेतु वन भूमि का ली० नि० विनाय / संस्था के पक्ष में परत सफाया प्रमाणपत्र एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवश्यक
प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार के विषय में ग्राम पंचायत गंगोड़ा (रापड़) द्वारा दिनांक 8/01/2015 का सम्पूर्ण ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रस्ताव एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि में सड़क में अनारक्षित जनपद पत्र निर्मित करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
समस्त सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि इतने वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गंगोड़ा (रापड़) के
ग्रामवासियों को इतने वन भूमि ली० नि० वि० प्रस्ताव एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत गंगोड़ा (रापड़)
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
जनपद प्रति प्रमाण पत्र 82

छायाप्रति प्रमाणित
राज्य सरकार
ग्रामीण विकास, लो० नि० वि०
रानीखेत

ग्राम पंचायत गंगोड़ा
वि० ख० - भिकियासैन (अल्मोड़ा)

दिनांक 8-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 27/05

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति की प्रमोसिजों का नाम	हस्ताक्षर
①	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
②	रघुवीर देवी	रघुवीर देवी
③	Hemraj Negi	Hemraj Negi
④	भागरणी देवी	भागरणी देवी
⑤	पानगुप्त देवी	पानगुप्त देवी
⑥	बालम कुमार	बालम कुमार

- ⑦ लक्ष्मी देवी
⑧ देवराज
⑨ प्रेमसिंह

महेश्वरी देवी
देवराज

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत में
विशेष अधिकारी

रघुवीर सिंह

सरपंच,
ग्राम पंचायत रापड
पो. श्री. पासी (चौकलिया)
जिला - बलमौरा.

आचार्य प्रमाणित
रापड अधिकारी
ग्राम पंचायत रापड, लोडनोपि
राजीव

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में राफट - जीनापानी - मसैडा
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नौधरिया / चरही
तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरीकृत

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरीकृत परियोजना के निर्माण हेतु (
X हे० आरक्षित वन भूमि X हे० विविध सार्वजनिक भूमि 2.160 हे० वन पंचायत भूमि 1.080 हे०) अर्थात् कुल 3.24
हे० वन भूमि का लौ० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाप्ति करार हेतु आरक्षित
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौधरिया द्वारा दिनांक 9-1-05 को सम्बन्धित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा गरीब आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गरीब आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य न
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो स
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो स
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौधरिया / चरही
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लौ० नि० वि० प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव विमला देवी
ग्राम पंचायत नौधरिया
पञ्जाब नगर निगम 532

पञ्जाब नगर निगम
पञ्जाब नगर निगम, लो० नि० वि०
रानीखेत

ग्राम प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत
प्रधान

ग्राम पंचायत नौधरिया
वि० ख० - भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रमोद
सदस्य
ग्राम पंचायत नौधरिया
भिकियासैन (अल्मोड़ा)

दिनांक 8-1-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत नौधरिया / धारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर
1-	बाबूजी सिंह	बाबूजी
2-	दीवान सिंह	दीवान सिंह
3-	वृषपाल सिंह	वृषपाल
4-	पुन सिंह	पुन
5-	जोगा राम	जोगा राम
7-	इ-इ राम	इ-इ राम

ग्राम प्रधान नरसिंह

प्रधान

ग्राम पंचायत नौधरिया
वि०ख०-शिकियासेन (अल्मोडा)

पुन सिंह

सदस्य
ग्राम पंचायत नौधरिया
शिकियासेन (अल्मोडा)

छायाप्रति प्रमाणित

[Signature]

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

QUESTION

Write up a report on the use of the following in the study of the life cycle of a plant.

Plant	Life Cycle
1. <i>Arabidopsis thaliana</i>	1. Seedling stage
2. <i>Arabidopsis thaliana</i>	2. Vegetative stage
3. <i>Arabidopsis thaliana</i>	3. Flowering stage
4. <i>Arabidopsis thaliana</i>	4. Seedling stage
5. <i>Arabidopsis thaliana</i>	5. Seedling stage

Write up a report on the use of the following in the study of the life cycle of a plant.

Write up a report on the use of the following in the study of the life cycle of a plant.

Write up a report on the use of the following in the study of the life cycle of a plant.

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23

राज्य (विनियम) - 2000

वन अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील जिला
20/03/2023

अनापत्ति प्रमाण पत्र
सुसहाय्य में जनपद के अन्तर्गत परियोजना
को निर्माण हेतु (.....) हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल खोयम भूमि..... है।
वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल 2.8.8.8 हे० वन भूमि का
विभाग/संरक्षण के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक व
सरपंच ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि न
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अधवा किसी न
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अधवा गैर आदिवासी न
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

सर्वों के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारि
किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भू
प्रयोक्तो एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/.....
ग्राम सचिव

सत्यापित प्रमाणित

.....
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
मि० 20/03/2023 - मि० 20/03/2023

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अधवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तत्पुसार उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 18/8

ग्राम सभा की सम्पत्ति के लिये की जा रही है

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...

हस्ताक्षर

ग्राम-प्रधान

ग्राम-प्रधान

ग्राम-प्रधान

ग्राम-प्रधान

ग्राम-प्रधान

परियोजना का नाम -

शपथ जीवा पानी मोटर गाडी की निर्माण हेतु ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण --पत्र

ग्राम पंचायत का नाम करगीना / झौनची
 तहसील अमियावा/मं जिला अमियावा
 अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्रयत

उक्त प्रयोजन के अन्तर्गत अग्रयत परियोजना के निर्माण हेतु
X हेतु आवेदित वन भूमि X हेतु निर्मित सैलम भूमि 2.16.0 हेतु वन पंचायत भूमि 1.08.0 हेतु अर्थात् कुल 3.24.0
 हेतु वन भूमि का सी 0 नि 0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाप्ति करने हेतु आलेख
 प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करगीना / झौनची द्वारा दिनांक 08/01/2018 सन्तुष्ट ग्राम सभा / ग्राम पंचायत को व
 न प्रयोजन एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनुरोधित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
 अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आवेदित अथवा किसी और आवेदिकारी का कब्जा / कोई कार्य है अथवा नहीं।
 उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आवेदिकारी अथवा और आवेदिकारी का कब्जा / कोई कार्य न
 किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो स
 चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करगीना / झौनची
 ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सी 0 नि 0 विभाग प्रयोजन एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दे दे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत अधिकारी अधिकारी
 दिनांक 08/01/2018
 ग्राम पंचायत के अध्यक्ष

परियोजना प्रमाणित
अग्रयत
 परियोजना प्रमाणित
 परियोजना प्रमाणित

ग्राम सभा / ग्राम सभा
 ग्राम सभा
 ग्राम पंचायत झौनची
 ग्राम पंचायत झौनची
 ग्राम पंचायत झौनची
 ग्राम पंचायत झौनची

प्रा.सं.प - 23.1

दिनांक 08-01-2023 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत करीमपुर / पानीपत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की प्रगतिशीलता के नाम	हस्ताक्षर
1	हरीश च-इ	हरीश च-इ
2	किशोर च-इ	(किशोर च)
3	दयाल राय	दयाल राय
4	दय राम	दय राम
5	जीवन च-इ	जीवन च-इ
6	किशोर च-इ	किशोर च-इ

31/5/2023

ग्राम प्रधान / सरपंच
सुनील कुमार

पंचायत समिति, पानीपत

पिपरा, पानीपत जिला

पिपरा, पानीपत जिला

हस्ताक्षर: मि. वि. प्रसाद (सि.स.प.)

आयापति प्रमाणित

Sunil Kumar
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअर मंडि
पानीपत

परियोजना का नाम :-

जलपद अल्मोड़ा में राण्ड - जीनापानी - महीडा मोटर
मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सेमेली (खोली) ग्राम
तहसील मिनामोडा जिला अल्मोड़ा

प्रस्तावक ने जलपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अपराध परियोजना के निर्माण हेतु

X हेतु आवेदित वन भूमि X हेतु निर्धारित जलपद भूमि 2.160 हेतु वन पंचायत भूमि 1.980 हेतु अर्थात् कुल 3.240
हेतु वन भूमि का अपराध निर्माण / संस्था के पक्ष में जलपद सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षीय करण हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोली (खोली) द्वारा दिनांक 8-01-15 को सचिव ग्राम जना / ग्राम पंचायत के हेतु
ने प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के जलपद में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्माण करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2005 के चर्चानों के तहत आवेदित वन भूमि में आवेदित अधिकांश भूमि ग्राम पंचायत के कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।

संस्थान सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आवेदित अथवा ग्राम पंचायत की कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा
चर्चा के उपरान्त ग्राम जना द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खोली (खोली)
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अपराध निर्माण प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्र पर अल्मोड़ा ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत सोल
ग्राम पंचायत सोल
ग्राम पंचायत सोल

ग्रामपंचायत प्रमाणित
अध्यक्ष अभियन्ता
प्राचीन खण्ड, लोणमण्ड
समीक्षित

क्र.सं/पं	ग्राम सभा में उपस्थित वारिड की. नाम व. संकेतों	हस्ताक्षर
1-	श्री. - श्री. गजेंद्र सिंह	
2-	श्री. - श्री. राम सिंह	
3-	श्री. - श्री. राम सिंह	
4-	श्री. - श्री. राम सिंह	
5-	श्री. - श्री. राम सिंह	

प्रधान
गणपति प्रसाद/साहू
नि०ख०- भिकियारैन (अल्गाद)

प्राप्तकालि प्रमाणित
 राजेश्वर
 राजेश्वर अग्रिमना
 प्राप्तकालि प्रमाणित, लोणजिनिनि
 प्राप्तकालि प्रमाणित, लोणजिनिनि
 प्राप्तकालि प्रमाणित, लोणजिनिनि

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....25.02.15.....at time..3:00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 3.240... hect. for the Construction of ...Rajpur Zameen Majhara.....M/R..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

Vmm
25.02.15
विनोद कुमार सुमन,
डी.डी.ओ.

(Full name of the official seal of the District Collector)

विनोद कुमार सुमन
Vmm
सहायक कमिश्नर
ग्रामीण विकास, लोअरमोरा
रानीखेत

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

25.02.15
Signature
बृहन्मोक्ष

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudrapur

No :.....

Dated: 25.02.2020

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Rocognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...3.2.4.0.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of

Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....*Rajendra Singh Neghera M.R.*.....

(Purpose for diversion of forest land) in *Almora*.....district falls within jurisdiction of.....village(s) in *Bhujyain* Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *3.240*..Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribale Groups, and pre-agricultural communities.

Encl:As above

[Signature]
 25.02.2020
 District Collector

(Full name of the official seal of the District Collector)

[Signature]
 प्रमुख अधिकारी
 ग्रामीण विकास
 राजीव

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.4

राज्य-स्तर पर-गहूँ-गन्ना-मूँग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद..... के अन्तर्गत प्रस्तावित राजस्व.....
परियोजना के निर्माण हेतु 3.240 हे० वन भूमि 05.15.15 (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारोषण लाइन, ओ०एफ०सी० केबिल व
पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

विद्या तन्नाज कल्याण अधिकारी
राज्योद्धार

प्रमाणित

राज्य

राज्यक दफ्तरी

प्राचीन पण्ड. लोभनसि०

रानीखेत

25/05/15

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

21/10/2016 4:45 PM 10/10/2016

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संयुक्त निरीक्षण

विरोधना का नाम - रापड़ जीनापानी मझोडा मोटर मार्ग ।

आज दिनांक 18.10.2016 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सड़का राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र उस्वारी मंडोल रानीखेत जिला जल्मीडा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का स्थान निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से श्री कुन्दनपुरी गोस्वामी राजस्व उपनिरीक्षक तथा वन विभाग की ओर से श्री आनन्द सिंह परिहार वन्यजक, श्री (1) श्री (2) वन क्षेत्राधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री नन्दन सिंह बिष्ट, अमीन / कुंठ मीनू देवी, व निष्ठ अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लोनिखेत, रानीखेत द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त ग्राम सड़का की 6.480 हे० भूमि रापड़ जीनापानी मझोडा मोटर मार्ग हेतु उपलब्ध करायी गयी । संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी ।

अमीन
प्रांतीय खण्ड लोनि
वि रानीखेत

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोनि वि.
रानीखेत

रापड़ कुंठ निरीक्षक
रापड़ कुंठ
रापड़ कुंठ

अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोनि
वि. रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड लोनि वि.
रानीखेत

वन क्षेत्राधिकारी
शितलाखेत (जल्मीडा)

संयुक्त निरीक्षण हेतु रानीखेत
प्रांतीय खण्ड लोनि वि.

Sanan

परियोजना का नाम :-

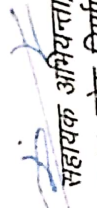
जनपद अल्मोड़ा में रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण। लम्बाई 16.200 किमी. (3.240 है०)।

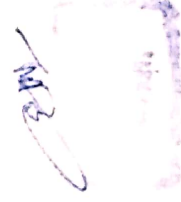
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में रापड़-जीनापानी-मझेड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण 16.200 किमी. (6.480 है०) या 7.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उचित सिविल भूमि उपयुक्त है।

ह./-
प्रभागीय वनाधिकारी


अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




उद्देश्य
वृक्षारोपण
रापड़


वृक्षारोपण अधिकारी,
रापड़। वन प्रभाग।


तहसीलदार भिकिवाडी,
रापड़। वन प्रभाग।
उप निदेशिका,
अभियान (रापड़)।


वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत
वन प्रभाग वलमोड़ा


उप निदेशिका,
अभियान (रापड़)।


प्रतिहस्ताक्षरित
विभागाध्यक्ष,
रापड़।

नकल खतोनी

दंगोर ज० वि० खतोनी ग्राम सड़का रा० उ० नि० भेत गड्यारी तहसील रानीखेत
विषय :- रापड़ जीमापनी मोटर मार्ग में ग्राम सड़का रा० उ० नि० भेत गड्यारी तहसील रानीखेत किमा
उम्माडा की 6.480 हे० घूमि वन विभाग के नाम नामन्तरण। हस्ताक्षर के सम्बन्ध में।

नाम खातेदार	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)
बन पंचायत	2079	0.243
	2082	0.473
	2083	0.415
	2158	0.208
	2171	0.368
	2172	0.208
	2173	0.358
	2200	0.265
	2208	0.230
	2209	0.153
	2210	0.128
	2271	0.125
	2373	0.440
	2400	0.770
	2567	0.180
	2568	0.600
	2590	0.063
	2591	1.063
	2600	0.053
	2602	0.673
	2603	2.250
	2604	0.480
	2605	1.500
	2606	2.250
	2616	0.191
	2617	0.090
	2618	7.048
	2619	1.560
योग	28	22.391

ब्राह्मदेश संख्या 2173/XVII (II) 2012-18 (120)
2010 दिसम्बर 2012 तथा जिलाधिकारी कार्यालय भुमनाडा
के आदेश संख्या 6084/ग्यारह-20/2020-21 दिनांक
23 जुलाई 2021 के क्रम में खेत संख्या 2400 हे०
0.770 हे०, खेत संख्या 2567 हे० 0.180, खेत संख्या
2568 हे० 0.600 हे०, खेत संख्या 2591 हे० 1.063 हे०
खेत संख्या 2602 हे० 0.673, खेत संख्या 2603 हे०
2.250 हे०, खेत संख्या 2604 हे० 0.480 हे०, खेत संख्या
2605 मध्ये हे० 0.464 कु० 6.480 हे० घूमि सिक्कि
घूमि को वन विभाग प्रभागीय वनाधिकारी उम्माडा के
प्रशासिक नियन्त्रण में नामान्तरित किया गया।

महोदय,

असल से नकल खतोनी तैयार की।

M. K. K.
राजस्व एवं मिनीमार्क

अनन-गड्यारी (प्र०)
तहसील रानीखेत (अनन-गड्यारी)

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार

कार्यालय उप जिलाधिकारी, वि. वि. 1/1/1/1
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र वि. वि. 1/1/1/1
उपखण्ड स्तरीय समिति,

राज उपखण्ड राज परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार
(राज हे० आरक्षित वन भूमि, राज हे० सिविल एवं सोयम. वन भूमि हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल राज हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील वि. वि. 1/1/1/1) की दिनांक 8-2-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार उपजिलाधिकारी वि. वि. 1/1/1/1 अध्यक्ष
- 2- श्री राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार उप प्रभागीय वनाधिकारी राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार उप जिलाधिकारी
- 3- श्री राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार सहायक समाज कल्याण अधिकारी राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार सदस्य/सचिव
- 4- श्री राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार बी०डी०सी० क्षेत्र राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार जिला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार
परियोजना हेतु.....हे० वन
भूमि राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राज - जिलापानी - अक्षेश मोर मार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 32001/1/1 परिक्षेत्र के अन्तर्गत
हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद
82001/1/1

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद.....
32001/1/1

प्रमाणित
प्रत्यक्ष अनियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0न0वि0
रानीखेत